IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत नयी शिक्षा नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण

डॉ. कौशलेन्द्र विक्रम सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर– समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय पिहानी, हरदोई

सारांश

नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह बड़ा बदलाव किया गया है। इस नीति को अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति को प्राचीन भारतीय ज्ञान और विचार की परंपरा के आलोक में तैयार किया गया है। भारतीय संस्कृति प्राचीन समय से ही ज्ञान और विज्ञान में समृद्ध रही है। नई शिक्षा नीति में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहु स्तरीय खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को इस तरह तैयार किया जाएगा ताकि वस्तु को रटने के बजाय उसे समझने की ओर बच्चों को प्रेरित किया जा सके और बच्चों में कौशल तथा आलोचनात्मक क्षमता का विकास किया जा सके ताकि बच्चे उचित–अनुचित का भी भेद कर सके नई शिक्षा नीति में नीतिगत बदलाव किए गए हैं लेकिन उनके क्रियान्वयन में व्यवहारिक जटिलताएं भी विद्यमान हैं।

मूल शब्दः– नई शिक्षा नीति 2020, प्राचीन भारतीय ज्ञान, कौशल तथा आलोचनात्मक क्षमता का विकास, खोज आधारित शिक्षा, व्यवहारिक जटिलताएं।

प्रस्तावना–

शिक्षा का उद्देश्य समाज को केवल गतिशील बनाये रखना ही नहीं है, बल्कि नागरिकों को समाज के मूल्यों एवं मानकों के अनुरूप तैयार करना है। शिक्षा व्यक्तित्व को रूपांतरित करती है। डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक विकास की प्रक्रिया मानते हैं तथा शिक्षा को ऐसा साधन मानते हैं जो व्यक्ति तथा समाज को प्रगति देता है एवं विकास को गति प्रदान करता है। उनके अनुसार बालक के साथ प्रेम तथा सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिये। इससे वह स्वाभाविक रूप से विकसित होता रहता है। बालक के स्वतन्त्र एवं स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है कि अध्यापक एवं माता–पिता द्वारा उन्हें अपनत्व प्राप्त हो क्योंकि इस भाव से प्रेरित हो बालक अपने मन में दबी जिज्ञासा तथा

महत्वाकांक्षा को बाहर लायेगा। जिससे उसके अन्तर्निहित क्षमताओं को जानकर उसके व्यक्तित्व के अनुसार शिक्षा प्रदान की की जा सके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी मत है कि शिक्षा व्यक्ति का अधिकार है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य रोजगार के साथ—साथ व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास करना है।

शिक्षा नीति में परिवर्तन 34 वर्ष बाद हुआ है। 1968 और 1986 के बाद तीसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है। नई शिक्षा नीति का प्रारूप डॉ० के० कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति को प्राचीन भारतीय ज्ञान और विचार की परंपरा के आलोक में तैयार किया गया है। भारतीय संस्कृति प्राचीन समय से ही ज्ञान और विज्ञान में समृद्ध रही है। ऋषि मुनियों की परंपराओं से हमें समाज को देखने की वैज्ञानिक दृष्टि मिलती है। भारतीय परंपरागत चिंतन पाश्चात्य समाजों के उपभोक्तावादी मानसिकता की तरह ना होकर बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल अपनाने वाला है। धर्म और विज्ञान भारतीय परंपरा में विरोधाभासी ना होकर बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई शिक्षा नीति प्राचीन ज्ञान, कला, नृत्य, संगीत आदि को पुनः महत्व प्रदान करती है, ताकि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में शैक्षणिक संस्थाओं की नवीन भूमिका सुनिश्चित हो सके।

सर्वांगीण विकास और नई शिक्षा नीति :—

नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर देती है। नई शिक्षा नीति में इसके लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं।

1- बच्चों के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की उम्र में हो जाता है। इस अवस्था में पर्याप्त शारीरिक और मानसिक विकास आवश्यक है। नई शिक्षा नीति में इस दिशा में प्रावधान किया गया है कि सभी बच्चों को इस उम्र में पोषण के साथ उचित शिक्षा दी जा सके ताकि शारीरिक और मानसिक विकास के साथ—साथ बच्चे सामाजिक मूल्यों और मानदंडों को सीख सकें। 2030 तक इस उम्र तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।

2- नई शिक्षा नीति में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहु स्तरीय खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है, जैसे अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इनडोर व आउटडोर खेल, पहेलियां और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए इसके साथ—साथ अन्य सार्वजनिक स्वच्छता, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, मानवीय संवेदना तथा अन्य सामाजिक कार्य करने और आपसी सहयोग को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज—संवेगात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्या ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है।

3- इस नीति का उद्देश्य पूर्व—प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना है। 3—6 आयु वर्ग के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित की गई है। शिक्षा का यह मॉडल माता—पिता दोनों के साथ—साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा।

4- देश भर की सभी स्थानीय भाषाओं में रचा गया साहित्य मुख्य रूप से बाल साहित्य को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए स्थानीय पुस्तकालय में बड़ी मात्रा में पुस्तके उपलब्ध कराई जाएंगी।

5- जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो सीखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए पुष्टाहार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है तथा प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग आदि के माध्यम से बच्चों के सम्यक विकास के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

6– पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को इस तरह किया जाएगा ताकि वस्तु को रटने के बजाय उसे समझने की ओर बच्चों को प्रेरित किया जा सके और बच्चों में कौशल तथा आलोचनात्मक क्षमता का विकास किया जा सके ताकि बच्चे उचित अनुचित का भी भेद कर सकें।

7– प्रयोग के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की बात कही गई है। प्रायोगिक आधारित अधिगम को अपनाया जाएगा जिसमें अन्य चीजों के अलावा करके सीखना तथा प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा तथा कहानी आधारित शिक्षण शास्त्र को प्रत्येक विषय में एक मानक शिक्षण शास्त्र के तौर पर देखा जाएगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों के बीच संबंधों की खोज को प्रोत्साहित किया जाएगा।

8– अनुभव आधारित अधिगम पर विशेष बल दिए जाने के अंतर्गत कला समन्वित शिक्षण को कक्षा प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाएगा जिससे न सिर्फ कक्षा ज्यादा आनंदपूर्ण होगी बल्कि भारतीय कला और संस्कृति के शिक्षण में समावेश से भारतीयता से भी बच्चों का परिचय हो पाएगा। इस एप्रोच से शिक्षा और संस्कृति के परस्पर संबंधों को भी मजबूती मिलेगी।

9– खेल समन्वय एक और क्लास–करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसके तहत स्थानीय खेलों सहित विभिन्न शारीरिक गतिविधियों का शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, ताकि परस्पर सहयोग, स्वतः पहल करना, स्वयं निर्देशित होकर कार्य करना, स्व–अनुशासन टीम भावना, आदि जैसे कौशल विकसित करने में सहायता हो सकेगी। खेल समन्वय अधिगम कक्षा के दौरान होगा ताकि छात्रों को फिटनेस को एक आजीवन दृष्टिकोण के रूप में अपनाने और फिट इंडिया मूवमेंट में परिकल्पित किए गए अनुसार फिटनेस के स्तर के साथ–साथ संबंधित जीवन कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

10– नई शिक्षा नीति में यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी में जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं। उसके अंदर छुपे हुए प्रतिभा को खोज कर उसका पोषण करना चाहिए। यह प्रतिभाएं अलग–अलग रुचियों प्रस्तावों और क्षमताओं के रूप में खुद को व्यक्त कर सकती हैं। जो छात्र किसी दिए गए दायरे में विशेष रूचि और क्षमताओं को दिखाते हैं उन्हें उस दायरे को सामान्य स्कूली पाठ्यक्रम से परे भी अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षक शिक्षा में विद्यार्थियों की प्रतिभाओं और रुचियों की पहचान और उन्हें बढ़ावा देने के तरीके शामिल होंगे। एनसीईआरटी और एनसीटीई प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए दिशानिर्देश विकसित करेंगे। बी.एड. कार्यक्रमों में भी प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा में विशेषज्ञता अर्जित की जा सकेगी।

11– देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा जिसमें स्कूल से लेकर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर जरूरी समन्वय के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी छात्र सभी स्तरों पर जिनमें उन्होंने क्वालीफाई किया है उनमें भाग ले सकें।

12– इंटरनेट और स्मार्टफोन तथा टेबलेट धीरे–धीरे प्रत्येक घरों और स्कूलों में उपलब्ध हो जाएंगे तब क्विज प्रतियोगिताओं, आकलन संवर्धन सामग्री वाले ऑनलाइन ऐप और साझा हितों के लिए ऑनलाइन समुदाय विकसित किए जाएंगे और सभी उपरोक्त चीजों को समृद्ध बनाने के लिए काम करेंगे जैसे माता–पिता और शिक्षकों की उचित देखरेख में विद्यार्थियों के लिए सामूहिक गतिविधियां। स्कूल चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट कक्षा विकसित करेंगे ताकि डिजिटल शिक्षणशास्त्र का उपयोग हो सके और उसके द्वारा ऑनलाइन संसाधनों और सहयोग के साथ–साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया को समृद्ध किया जा सके।

13– भारत के प्रत्येक राज्य/जिले में विशेष डे–टाइम बोर्डिंग स्कूल "बाल भवन" स्थापित किए जाएंगे। इस बोर्डिंग स्कूल का उपयोग खेल, करियर, कला से जुड़ी गतिविधियों में भागीदारी के लिए किया जाएगा।

चुनौतियां:–

नई शिक्षा नीति में नीतिगत बदलाव किए गए हैं लेकिन उनके क्रियान्वयन में व्यवहारिक जटिलताएं विद्यमान हैं। नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम में शारीरिक गतिविधि एवं खेलकूद को शामिल किया गया है लेकिन अभी भी अधिकतर विद्यालयों में ना तो व्यायाम शिक्षक की व्यवस्था है और ना ही आधारभूत संरचना है। विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए बहुविषयक शिक्षा तथा शिक्षणेत्तर गतिविधि को शामिल किया गया है परंतु विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए संस्था के स्तर पर विषय विशेषज्ञों की तैनाती नहीं है। मूल्यांकन के लिए आंतरिक मूल्यांकन और मिडटर्म तथा सेमेस्टर प्रणाली जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसके कारण उच्च शिक्षा में संस्थान का अधिकतर समय परीक्षाओं के आयोजन में ही नष्ट हो जाता है। जिसके कारण अध्ययन हेतु कक्षाओं का समय संकुचित हो गया है। जिन राज्यों में नई शिक्षा नीति को तत्काल रुप से बिना किसी तैयारी के लागू कर दिया गया है वहां पर अनेक समस्याएं निकल कर सामने आ रही हैं। नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा का उपबंध करती है जबकि व्यावहारिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दे रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना तथा शिक्षकों की कमी है जिसके कारण केवल गरीब बच्चे सरकारी विद्यालयों को प्राथमिकता दे रहे हैं। निजी स्कूल महंगे हैं इसके बावजूद वहां पर सरकारी स्कूलों से पलायन जारी है। उच्च शिक्षा में अधिकतर स्ववित्तपोषित विद्यालयों में शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है जिसके कारण शिक्षकों को यूजीसी के मानक के अनुरूप वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसका एक दूसरा पक्ष यह भी है कि उच्च शिक्षा में सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था ना किए जाने से स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की संख्या ज्यादा है तथा उसके लिए विद्यार्थियों को स्वयं भुगतान करना पड़ता है। नई शिक्षा नीति में एकल पाठ्यक्रम को अपनाया गया है लेकिन इसके बावजूद कई विश्वविद्यालयों ने नई शिक्षा नीति को स्वीकार तो लिया है लेकिन उन्होंने पाठ्यक्रम का चुनाव अपने स्तर पर किया है।

निष्कर्ष :–

21वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। नई शिक्षा नीति उन आवश्यकताओं की पूर्ति में बड़ा कदम है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ–साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का रूपांतरण करना शिक्षा का मुख्य ध्येय है। आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति में समाज से लेकर पर्यावरण तक को क्षति पहुंची है। नागरिकों में समाज के प्रति जवाबदेही, मूल्यों एवं मानकों तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का बोध कराने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति रोजगार के साथ–साथ कौशल विकास और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। हालांकि नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद कई सारी जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। आधारभूत संरचना का अभाव तथा शिक्षा में अपर्याप्त निधि एक समस्या का विषय है। दृढ़ संकल्प के साथ इस दिशा में आगे बढ़ने से आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है तथा नई शिक्षा नीति को सही से क्रियान्वित कर भारतीय शिक्षा पद्धति को और सुदृढ़ किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप नए भारत के निर्माण में सक्षम नागरिकों को शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा तैयार किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

1– एल्विन "सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन", हार्पर्स, 26 (1986), पृष्ठ 25.

2– भट्टाचार्य श्रीनिबास "सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ़ एजुकेशन", अटलांटिक, नई दिल्ली (2003).

3– हारलाम्बस, एम "सोशियोलॉजी" ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली (1980).

4- https://pdffile.co.in/national-education-policy-nep-2022/

5-http://www.raijmr.com/ijrsml/wp-content/uploads/2021/01/IJRSML_2017_vol05_Sp.issue_12_Eng_25.pdf

6-https://timesofindia-indiatimes-com.translate.goog/readersblog/ray-of-thought/new-education-policy-advantages-disadvantages-32468/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc

7–https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf